

संख्या-926/XIV-1/2017-5(02)/2017

प्रेषक,

आनन्द स्वरूप,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

सहकारिता गान्ना एवं चीनी अनुभाग-1
विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "सहकारिता न्यायाधिकरण" की
विभिन्न मर्गों हेतु वित्तीय स्वीकृति।
देहरादून दिनांक 24 जुलाई, 2017

महोदय,

उपयुक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-2380/लेखा/बजट प्रावि0/2017-18 दिनांक 04 जून, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत प्रस्तर-5 में उल्लिखित "सहकारिता न्यायाधिकरण" की विभिन्न मर्गों में ₹55,23,000.00 (पचास लाख तेईस हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट प्रत्याशा से कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा। मानक मद-01-वैतन-03-महगई मत्ता-06-अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
- (2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
- (3) बजट मैन्युअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में ठीक पूर्व माह की सूचना बी0एम0-5 प्रपत्र पर आहरण एवं वितरण

(2)

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था निबंधक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जायेगा। वयनबद्ध तथा अवयनबद्ध मदों के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त पत्र दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(6) वयनबद्ध मदों का व्यय मासिक आधार पर किस्तों में किया जायेगा। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा जो भी कम हो, के अन्तर्गत रहेगी।

(7) अवयनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में भित्तव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में भित्तव्ययता हेतु स्पष्ट कार्ययोजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(8) आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्भावित व्यय की फेंजिंग की सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-001-निर्देशन तथा प्रशासन, 05-सहकारिता न्यायाधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे जाला जायेगा।

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बजट प्राविधान	प्राविधान के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अवशेष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
01	वैतन	6719	3360	3359
02	भजदूरी	70	23	47
03	महगाई भत्ता	403	201	202
04	यात्रा भत्ता	10	03	07
05	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	10	03	07
06	अन्य भत्ते	470	157	313
07	मानदेय	10	03	07
08	क्यालख व्यय	100	22	

18	प्रकाशन	10	03	07
19	विज्ञापन द्विकी एवं विज्ञापन व्यय	0	0	0
22	आतिथि व्यय विशेषक भरता	25	08	17
26	मशीनें और सज्जा / उपकरण और सयन	50	17	33
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300	100	200
29	अनुरक्षण	10	03	07
42	अन्य व्यय	0	0	0
44	प्रशिक्षण	10	03	07
45	अवकाश यात्रा व्यय	100	33	67
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का कय	60	20	40
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	50	17	33
	योग-	10062	4539	5523

(रूपपत्र लाख तेईस हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आनन्द स्वरूप)

अपर सचिव।

संख्या-१२६(1)/XIV-1/2017, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, ओबर्ग्य बिलडिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त-4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून उत्तराखण्ड।
4. बजट निदेशालय, सचिवलय परिसर, देहरादून।
5. सचिव, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवलय परिसर, देहरादून।